हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्षः 11 अंकः 97 लखनऊ, गुरुवार 20 नवंबर 2025 पृष्ठः 04 मूल्यः 01 रूपये

सीएम योगी ने नहर व्यवस्था सुधार के लिए 95 नई परियोजनाओं को दी मंजूरी

–नौ लाख किसान होंगे लाभांवित

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रदेश की नहर व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 95 नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों को समयबद्ध सिंचाई उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। करीब 394.53 करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 36 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित होगी, जिससे लगभग 9 लाख किसान और ग्रामीण आबादी को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। सीएम बुधवार को अपने आवास पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे 273 हेक्टेयर विभागीय राजकीय भूमि को संरक्षित भी किया जा सकेगा। उन्होंने सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश भी दिया। बैठक में बताया गया कि नहर पुनर्स्थापना से जुड़ी इन 95 परियोजनाओं में नहर प्रणाली के गैप्स में नहर निर्माण, हेड रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर, साइफन, फॉल तथा अन्य पक्की संरचनाओं का निर्माण शामिल है। नहरों के आंतरिक एवं बाह्य सेक्शन के सुधार, फिलिंग रीच में लाइनिंग के कार्य, क्षतिग्रस्त कुलाबों के पुनर्निर्माण, नहरों पर पुल–पुलियों के निर्माण एवं मरम्मत तथा नहर पटरियों पर खड़ंजा निर्माण को भी परियोजनाओं में शामिल किया गया है। बाउंड्रीवाल निर्माण भी प्रस्तावित निरीक्षण भवनों, कार्यालय भवनों तथा नहरों पर निर्मित पनचक्कियों के जीर्णोद्धार के साथ ही विभागीय भूमि की सुरक्षा हेतु बाउंड्रीवाल निर्माण भी प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से सिंचाई नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी और विभिन्न क्षेत्रों में जल उपलब्धता सुचारू होगी, विशेष रूप से पूर्वांचल, तराई, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को इनसे बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल निर्माण नहीं बल्कि जल प्रबंधन की दक्षता, किसान हित, कृषि उत्पादन

वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी किसान सिंचाई के अभाव में अपनी फसल प्रभावित न होने पाए। उन्होंने विभाग को अनुपयोगी भूमि के सर्वेक्षण और उसके सदुपयोग हेतु कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए ताकि इसके उपयोग से विभाग की आय वृद्धि हो सके। बाढ़ प्रबंधन की जनवरी से करें तैयारी सीएम ने बाढ़ प्रबंधन से जुड़े कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि सभी तैयारियां जनवरी माह से शुरू कर दी जाएं। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन से विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए ताकि समय रहते आगे की कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

निकाय चुनावों को लेकर महायुति में दरार? अमित शाह से मिले शिंदे, बताया– माहौल बिगाड़ रहे कुछ नेता

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह से मुलाकात की। यह मुलाकात इस वजह से भी चर्चाओं में रही, क्योंकि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर महायुति में विवाद छिड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इन अटकलों को राज्य कैबिनेट की बैठक में तब और बल मिला, जब शिवसेना शिंदे गुट के सभी मंत्रियों ने इस बैठक से किनारा कर लिया था। कैबिनेट बैठक से दूरी बनाने के बाद शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की थी। इस बैठक में फैसला लिया गया कि महायुति के सहयोगी दलों को एक–दूसरे के पार्टी पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करने से बचना चाहिए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का आनन–फानन में यह दिल्ली दौरा इसी मुद्दे पर राहत पाने के लिए किया गया है। वहीं, पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें बताया कि महायुति के कुछ नेता आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए अनुकूल राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शिंदे ने शाह से यह भी कहा कि टाली जा सकने वाली रुकावटें महायुति गठबंधन की जीत की गति में बाधा डाल सकती हैं और विपक्ष को अनुचित लाभ पहुंचा सकती हैं। उपमुख्यमंत्री ने शाह से बैठक के दौरान यह भी कहा कि गठबंधन सहयोगियों को एक–दूसरे की आलोचना करने से बचना चाहिए। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव 2 दिसंबर को होंगे, जबकि नगर निगम चुनाव जनवरी 2026 में होने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया बड़ा झटका, रद्द किया न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र को चार महीने के अंदर एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग गठित करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधिकरण सदस्यों और पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति, कार्यकाल और

सेवा शर्तों से संबंधित न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रमुख प्रावधानों को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने न्यायाधिकरणों पर कार्यपालिका के बहुत ज्यादा नियंत्रण पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के न्यायाधिकरणों के कामकाज, संरचना और सेवा शर्तों में व्यापक बदलाव लाने वाले न्यायाधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अधिनियम, 2021 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। पीठ ने कहा, हम केंद्र सरकार को राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग स्थापित करने के लिए इस फैसले की तारीख से चार महीने का समय देते हैं। फैसले में कहा गया, इस तरह के आयोग का गठन एक जरूरी संरचनात्मक सुरक्षा उपाय है जिसे देश भर के न्यायाधिकरणों की नियुक्ति, प्रशासन और कामकाज में स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अधिनियम की धारा 3 से 7 और 33 के साथ–साथ एक दर्जन से ज्यादा केंद्रीय कानूनों में किए गए कई संशोधनों पर ये चुनौतियां केंद्रित थीं। 137 पन्नों के फैसले में सीजेआई गवई ने साफ तौर से इन प्रावधानों को अमान्य करार दिया। इनमें से एक धारा 3 थी, जिसमें न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई थी। फैसले में कहा गया कि इस प्रतिबंध ने मनमाने ढंग से युवा और सक्षम अधिवक्ताओं और विशेषज्ञों को इससे बाहर रखा। इसने अधिनियम की धारा 5 को भी रद्द कर दिया, जिसमें न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष निर्धारित किया गया था। इसने धारा 3 के तहत न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया को भी रद्द कर दिया और खोज–सह–चयन समिति (SCSC) को प्रत्येक रिक्ति के लिए दो नामों के एक पैनल की सिफारिश करने के लिए बाध्य किया। अधिकांश न्यायाधिकरणों में, SCSC की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी ओर से नामित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करते हैं। इस समिति में दो केंद्रीय सचिव और एक अतिरिक्त सदस्य भी शामिल होता है, जो आमतौर पर न्यायाधिकरण का निवर्तमान या वर्तमान अध्यक्ष होता है. अगर वर्तमान अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति चाहता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की ओर से नामित सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को अतिरिक्त सदस्य के रूप में कार्य करना होगा।

PM मोदी ने जारी की किसान निधि की 21वीं किस्त

बोले– भारत जैविक खेती का वैश्विक केंद्र बनने की राह पर

एजेंसी

कोयंबटूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत जैविक खेती का वैश्विक केंद्र बनने की राह पर है और उन्होंने जोर देकर कहा कि यह देश की मूल और पारंपरिक संस्कृति है। बिहार में एनडीए की शानदार जीत के बाद मोदी ने अपने आगमन पर गमछा लहराते दर्शकों देखकर कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे बिहार की हवाएं उनसे पहले तमिलनाडु पहुंच गई हों। किसानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं यहां मंच पर आया, तो मैंने देखा कि कई किसान हवा में अपना गमछा लहरा रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे बिहार की हवा मुझसे पहले ही यहां पहुंच गई हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, प्राकृतिक खेती मेरे दिल के बहुत करीब का विषय है। मैं तमिलनाडु के सभी किसानों को इस अद्भुत दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रदर्शनी देख रहा था। मुझे कई किसानों से बात करने का अवसर मिला। किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, पीएचडी की है और फिर खेती कर रहे हैं, कोई नासा छोड़कर खेती कर रहा है, वे

कई युवाओं को तैयार कर रहे हैं और प्रशिक्षित कर रहे हैं। पीएम ने आगे कहा कि मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता हूं कि अगर मैं इस कार्यक्रम में नहीं आया होता, तो मैं अपने जीवन में बहुत कुछ खो देता। आज यहां आकर, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं तमिलनाडु के किसानों के साहस को सलाम करता हूं, परिवर्तन को स्वीकार करने की उनकी शक्ति को सलाम करता हूं। मोदी ने कहा, आने वाले वर्षों में मैं भारत की कृषि में कई बड़े बदलाव होते देख सकता हूं। भारत प्राकृतिक खेती का वैश्विक केंद्र बनने की राह पर है। हमारी जैव विविधता एक नया आकार ले रही है, देश के युवा कृषि को एक आधुनिक, व्यापक अवसर के रूप में देख रहे हैं। इससे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 11 वर्षों में देश के संपूर्ण कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आया है। हमारा कृषि निर्यात लगभग दोगुना हो गया है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने किसानों के समर्थन के सभी रास्ते खोल दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती उनके दिल के बहुत करीब है। प्राकृतिक खेती का विस्तार 21वीं सदी की कृषि की जरूरत है। हाल के वर्षों में, बढ़ती मांग के कारण खेतों और विभिन्न कृषि–संबंधित क्षेत्रों में रसायनों के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है। पीएम ने कहा, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। मिट्टी की नमी प्रभावित हो रही है और साल–दर–साल खेती की लागत बढ़ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस समस्या का समाधान फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती में ही मृदा संबंधी समस्याओं का समाधान है। उन्होंने कहा कि साथ ही जैविक खेती जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में भी मदद करती है। प्राकृतिक खेती का अपना स्वदेशी विचार है और यह देश की परंपराओं में निहित है और पर्यावरण के अनुकूल है। हमारा लक्ष्य प्राकृतिक खेती को पूरी तरह से विज्ञान–समर्थित आंदोलन बनाना होना चाहिए। प्राकृतिक खेती एक स्वदेशी भारतीय अवधारणा है जो कहीं और से आयातित नहीं है, बल्कि परंपरा से उपजी है और पर्यावरण के अनुकूल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में भारतीय कृषि में बड़े बदलाव होंगे। लग रहा बिहार की हवाएं पहले ही तमिलनाडु आ गईं बिहार में राजग की शानदार जीत के बाद मोदी ने तमिलनाडु आगमन पर लोगों की ओर से गमछा लहराने का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा था कि बिहार की हवाएं उनसे पहले ही तमिलनाडु में आ गई हों। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाला राजग अगले साल विधानसभा चुनाव में द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन से मुकाबला करेगा। विपक्षी गठबंधन एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से हटाने के लिए प्रयास कर रहा है।

सेना की वर्दी की नकल की तो होगी कानूनी कार्रवाई

युध्दक कोट पर मिला बौध्दिक संपदा अधिकार

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। सेना ने अपने नए कोट कॉम्बैट (डिजिटल प्रिंट) की डिजाइन पर विशेष बौद्धिक संपदा अधिकार हासिल कर लिए हैं। इसके बाद कोट की डिजाइन और छलावरण पैटर्न के अनन्य बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पूरी तरह से सेना के पास आ गए हैं। यह डिजाइन कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स, कोलकाता में डिजाइन आवेदन संख्या 449667–001 के तहत पंजीकृत हुआ है। यह आवेदन 27 फरवरी 2025 को दर्ज किया गया था और 07 अक्टूबर 2025 को पेटेंट ऑफिस के आधिकारिक जर्नल में प्रकाशित हुआ। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि किसी भी अनधिकृत संस्था की ओर से इस कोट का निर्माण, पुनरुत्पादन या व्यावसायिक उपयोग कानूनन अपराध है। उल्लंघन करने पर पेटेंट एवं डिजाइन

अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई होगी और क्षतिपूर्ति के दावों समेत कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। मंत्रालय ने बताया कि न्यू कोट कॉम्बैट को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), नई दिल्ली द्वारा सेना डिज़ाइन ब्यूरो के तत्वावधान में एक परामर्श परियोजना के रूप में डिज़ाइन और विकसित किया गया है। तीन–परतों वाले इस परिधान में उन्नत तकनीकी वस्त्रों का उपयोग किया गया है और इसमें एक एर्गोनॉमिक डिज़ाइन है जो विभिन्न जलवायु और सामरिक परिस्थितियों में आराम, गतिशीलता और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए अनुकूलित है। ये वस्त्र आराम और सुरक्षा के साथ युद्ध कार्यक्षमता के एकीकरण की दिशा में एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा निरंतर परिवर्तन और सैनिक कल्याण के प्रति सेना की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हैं। कोट की खासियत बाहरी परतरू डिजिटल रूप से मुद्रित कोट, जो विभिन्न भूमागों में परिचालन स्थायित्व और छिपाव के लिए डिज़ाइन किया गया है। आंतरिक जैकेटरू हल्के, सांस लेने योग्य सामग्रियों का उपयोग करके बनाई गई मध्य परत, जो गति को बाधित किए बिना गर्मी प्रदान करती है। थर्मल परत : आधार परत जो चरम मौसम में तापीय विनियमन और नमी नियंत्रण सुनिश्चित करती है।

इसरो को मिली बड़ी कामयाबी, CE20 क्रायोजेनिक इंजन के बूट-स्ट्रैप मोड स्टार्ट का किया सफल परीक्षण

एजेंसी

बंगलूरू। इसरो (ISRO) ने बुधवार को एलान किया कि उसने ब्20 क्रायोजेनिक इंजन के बूट–स्ट्रैप मोड स्टार्ट परीक्षण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है, जो लॉन्च व्हीकल मार्क–3 (LVM3) रॉकेट के ऊपरी चरण को ताकत देता है। इसरो ने बताया कि यह परीक्षण 7 नवंबर को महेंद्रगिरि स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स स्थित हाई–एल्टीट्यूड परीक्षण (HAT) सुविधा में वैक्यूम की परिस्थितियों में 10 सेकंड के लिए किया गया था। इसरो के मुताबिक ब्20 क्रायोजेनिक इंजन उड़ान में एक बार स्टार्ट करने पर 19 से 22 टन के थ्रस्ट स्तर पर संचालन के लिए पहले से ही योग्य है और इसे गगनयान मिशनों में उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में, इंजन का प्रज्वलन टैंक हेड प्रेशर में शुरू

होता है, जिसके बाद एक संग्रहित गैस स्टार्ट–अप सिस्टम का उपयोग करके टर्बोपंप स्टार्ट अप होता है। इसरो ने बताया कि भविष्य के मिशनों के लिए, बहु–कक्षा मिशनों की दिशा में लचीलेपन के लिए CE20 इंजन को उड़ान के दौरान कई बार फिर से शुरू करने की जरूरत होगी। एजेंसी ने कहा कि वर्तमान कॉन्फिगरेशन के साथ, हर बार फिर से शुरुआत के लिए एक अतिरिक्त स्टार्ट–अप गैस बॉटल और संबंधित प्रणालियों की जरूरत होती है, जिससे वाहन की पेलोड क्षमता में कमी आती है। उन्होंने बताया कि इसलिए बूट–स्ट्रैप मोड स्टार्ट प्राप्त करना जरूरी है, जहां इंजन बाहरी स्टार्ट–अप मदद के बिना स्थिर संचालन के लिए तैयार होता है।ए एजेंसी ने आगे कहा कि परीक्षण के दौरान, बूट–स्ट्रैप स्टार्टिंग को सुगम बनाने के लिए थ्रस्ट चौंबर और गैस जनरेटर दोनों में एक बहु–तत्व इग्नाइटर का उपयोग किया गया था। इस परीक्षण में थ्रस्ट चौंबर के प्रज्वलन के बाद गैस जनरेटर को टैंक हेड स्थितियों में प्रज्वलित किया गया और टर्बोपंप को स्टार्ट–अप सिस्टम के उपयोग के बिना चालू किया गया। इसके बाद बूट–स्ट्रैप मोड बिल्ड–अप और इंजन के स्थिर–अवस्था संचालन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। एजेंसी ने कहा, इस उपलब्धि के साथ इसरो ने बिना किसी सहायक स्टार्ट–अप प्रणाली के गैस–जनरेटर चक्र क्रायोजेनिक इंजन के बूट–स्ट्रैप मोड स्टार्टिंग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। जो शायद दुनिया में पहली बार हुआ है। ये भविष्य की एलवीएम3 उड़ानों की पुनः आरंभ क्षमता और मिशन लचीलेपन को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

जिम के नीचे गोदाम में मिली करोड़ों की कफ सिरप, लखनऊ नारकोटिक्स टीम की वाराणसी में रेड, जांच जारी

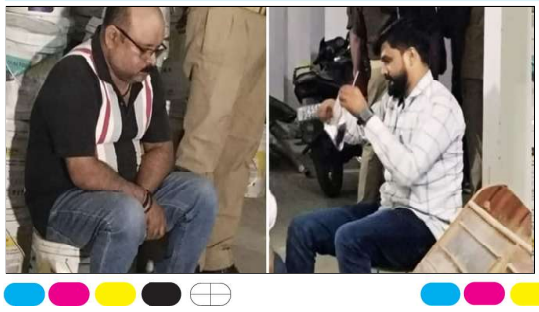

एजेंसी

लखनऊ। रोहनिया भदवर बाइपास पर एक गोदाम मे भारी मात्रा मे कफ सीरप पकड़ा गया। बुधवार को नारकोटिक्स विभाग लखनऊ ने रोहनिया पुलिस के साथ छापेमारी कर गोदाम का ताला तोड़ा था।

गोदाम के अंदर टीम घुसी तो पेंट की बाल्टी के नीचे छिपाकर रखा गया था भारी मात्रा में कफ सिरप रखी गई थी। जानकारी के अनुसार, गोदाम के ऊपर जिम चलाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार मे पकड़े गए सिरप की अनुमानित कीमत 1.5 से दो करोड़ रुपये बताई जा रही है। डीसीपी वरूणा जोन प्रमोद कुमार को गुप्त सूचना मिली थी। इसी के आधार पर एसीपी रोहनिया संजीव शर्मा और थाना प्रभारी राजू सिंह की टीम ने छापा मारा था। गोदाम किसी महिला प्रधान के पति का बताया जा रहा है। डीसीपी वरूणा के अनुसार, ड्रग विभाग और एएनटीएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस मौके पर जांच पड़ताल में जुटी है।

बांग्लादेश के NSA रहमान और भारत के डोभाल की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई अहम चर्चा

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। नई दिल्ली में बुधवार को बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) डॉ. खलीलुर रहमान और भारत के एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत दिया। शेख हसीना की सत्ता से बेदखली और मौत की सजा के बाद संबंधों में आई खटास के दौर में यह मुलाकात सुरक्षा और राजनीतिक स्तर पर जारी संवाद का सबसे उच्च स्तरीय कदम मानी जा रही है। यह बैठक कोलंबो सिक्योरिटी कंक्लेव (सीएससी) की सातवीं एनएसए स्तरीय बैठक से पहले हुई। बांग्लादेश हाई कमीशन के बयान के अनुसार दोनों एनएसए ने कोलंबो सिक्योरिटी कंक्लेव के कामकाज और प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। रहमान ने एनएसए डोभाल को बांग्लादेश के दौरे का निमंत्रण भी दिया। रहमान इस बार सीएससी बैठक में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

संपादकीय

पी के की उलझन भरी राजनीति

बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त खाने के बाद इंतजार था कि अब प्रशांत किशोर राजनीति में किस दिशा में बढ़ते हैं। मंगलवार को एक प्रेस कांफ्रेंस कर पी के ने स्पष्ट कर दिया है कि वे न बिहार छोड़ने वाले हैं, न राजनीति। यह जाहिर भी था। भले ही प्रशांत किशोर ने पहले ऐलान किया हो कि अगर जनता दल (यूनाइटेड) ने चुनाव में 25 से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज की तो वह राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन अब जेडीयू ने पी.के. के दावों से तिगुने से अधिक 85 सीटें जीती हैं। तो सवाल उठने लगे कि क्या अब पी. के. राजनीति को अलविदा कह देंगे। इसका जवाब उन्होंने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में दे दिया कि श्मैं उस बात पर बिल्कुल कायम हूं। अगर नीतीश कुमार की सरकार ने ये वोट नहीं खरीदे हैं, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पी.के. की पार्टी ने महिलाओं के खाते में 10 हजार देने को घूस भी बताया है। एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि जब आपने ये बयान दिया था, तब ये शर्तें क्यों नहीं बताईं थीं? इस पर प्रशांत किशोर ने कहा, मैं किस पद पर हूं कि इस्तीफा दे दूं? मैंने ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाऊंगा। मैंने राजनीति छोड़ रखी है, राजनीति कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन ये तो नहीं कहा है कि बिहार के लोगों की बात उठाना छोड़ देंगे।इन बातों से जाहिर है कि प्रशांत किशोर की राजनीति भी उनकी बातों की तरह उलझाने वाली है। जिसमें कोई स्पष्टता नहीं है और कभी भी अपने कहे से पलटने की गुंजाइश है। आखिर मौजूदा दौर में इस तरह के राजनेता ही सफल भी हो रहे हैं। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि श्ढाई तीन साल पहले वे व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। न तो सत्ता परिवर्तन कर सका और न ही व्यवस्था, लेकिन बिहार की राजनीति को जरूर प्रभावित किया है।बिहार की राजनीति को किस आधार पर प्रभावित करने की बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं, यह अब भी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि प्रभाव पड़ता है, तो जमीन पर दिखता है। फिलहाल तो बिहार में यथास्थिति ही कायम है। ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के नाम बदल सकते हैं, लेकिन सत्ता पहले भी भाजपा के हाथों में थी और अब तो दोगुनी ताकत के साथ आ चुकी है। शायद प्रशांत किशोर की राजनीति, साढ़े तीन साल पहले की गई उनकी पदयात्रा, बिहार चुनाव में 238 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने की रणनीति, चुनाव प्रचार में सत्तारुढ़ गठबंधन के साथ–साथ विपक्ष को भी निशाने पर लेना, ये सब भाजपा की दबी–छिपी मदद के ही तरीके थे। भाजपा यह अच्छे से जानती थी कि लोकसभा चुनावों के बाद इंडिया गठबंधन के उठाए मुद्दे जनता को प्रभावित करने लगे हैं। खासकर संविधान बचाने और जातिगत जनगणना, आरक्षण की सीमा बढ़ाने जैसे मुद्दे बिहार में निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर को आगे बढ़ाकर इन मुद्दों के बरक्स विकास और वंशवादी राजनीति के खिलाफ नैरेटिव तैयार किया गया। याद कीजिए कि प्रशांत किशोर के भाषणों में लालू प्रसाद के साथ–साथ तेजस्वी यादव पर भी हमला होता था, खासकर उनकी शैक्षणिक योग्यता पर पी. के. हमलावर होते थे। पी.के. की तरह ही असद्दुदीन ओवैसी और मायावती भी महागठबंधन के लिए वोट काटने वाले साबित हुए।चुनाव में प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि उनकी पार्टी श्या तो अर्श पर होगी या फर्श पर होगी।श्य नतीजे तो बता रहे हैं कि पार्टी फर्श पर आ गई है। एक भी सीट न जीतना और कई पर जमानत जब्त होना किसी सफल पार्टी के लक्षण नहीं हैं। और यह भी कोई नियम नहीं है कि चुनावी राजनीति में पहली बार ही सफलता मिल जाए। एक वक्त में भाजपा भी महज दो संसदीय सीटों वाली पार्टी थी। लेकिन उसकी विचारधारा स्पष्ट थी कि देश में हिंदुत्ववादी ताकतों को स्थापित करना है, राम मंदिर बनाना है, कश्मीर से 370 खत्म करना है आदि। प्रशांत किशोर की राजनीति में इस स्पष्टता का अभाव है। अगर वे बिहार के विकास की बात करते हैं, पलायन रोककर राज्य में ही लोगों को रोजगार मुहैया कराने और भ्रष्टाचार खत्म करने के मुद्दों के साथ चुनावी राजनीति में उतरे थे, तो यही मुद्दे महागठबंधन के भी थे। फिर उन्होंने आरजेडी या कांग्रेस का विरोध ा क्यों किया। इसी तरह वे आरक्षण या जाति आधारित व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं तो खुलकर भाजपा का साथ क्यों नहीं दिया। दो गठबंधनों में किसी एक के साथ जाने का विकल्प प्रशांत किशोर के पास था, अब भी है, लेकिन वे बिहार में अरविंद केजरीवाल की तर्ज वाली राजनीति कर रहे हैं।आम आदमी पार्टी ने जिस तरह दिल्ली फिर पंजाब और गोवा में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, वही काम प्रशांत किशोर ने बिहार में किया। अब भले वे अपनी हार की जिम्मेदारी ले रहे हैं।

राशिफल

मेष :– कोई छोटी बात भी परिवार कें तनाव का कारण बन सकती है। महत्वपूर्ण प्रयत्न की सार्थकता नये उत्साह का संचार करेगी। सामाजिक गतिविधियों में क्रियाशीलता बढ़ेगी। भावनात्मक अभिव्यक्ति से संबंध मधुर बनेंगे।

बृषभ :– हर घटना से आपको सीख लेने की जरूरत है। नये क्षेत्र में निवेश से पूर्व बुद्धिजीवियो से विचार–विमर्श करें। भविष्य के प्रति निराशाजनक विचारों को मन पर हावी न होने दें। नये व्यावसायिक यात्राएं करनी होंगी।

मिथुन :– निकट संबंधों में मधुर संवाद से अपनी सुन्दर छबि बनावें। कुछ महत्वपूर्ण अभिलाषाओ की पूर्ति होने के आसार हैं। सामान्य दिनचर्या के साथ बीत रहे जीवन में उत्साह का अभाव रहेगा।

कर्क :– भविष्य के प्रति मन में चिंताएं उत्पन्न होंगी। किसी कार्य को छोटा–बड़ा समझने के बजाए अपने कर्त्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन् करें। वर्तमान कार्य से मन में असन्तुष्टि उत्पन्न होगी। आलस्य का त्याग करें।

सिंह :– पारिवारिक दायित्वों की चिंता उत्पन्न होगी। स्वास्य के प्रति लापरवाही न बरतें एवं जीवन साथी के स्वास्य के प्रति ध्यान देवें। किसी बड़े आयोजन हेतु समुचित ब्यवस्था के लिए मन प्रयत्नशील होगा।

कन्या :– छोटी–छोटी पारिवारिक बातों को बाहरी लोगों से न कहें। भावना से उद्वेलित मन सगे–संबंधियों के सुख–दुख के प्रति चिंतित होगा। किसी नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी। पुरानी घटनाएं याद आएंगी।

तुला :– वक्त के साथ समझौता कर चलने की चेष्ठा करें। अपने कार्यक्षेत्र को ही अपनी पूजा समझे और अपने को उसी दिशा की ओर केंद्रित करें। रोजगार में अपनी क्षमता का पूर्ण लाभ उठाएंगे।

वृश्चिक :– जीवन में सही लक्ष्य व सुदृढ़ता को सुनिश्चित करें तभी जीवन में सही प्रगति कर सकते हैं। किसी पुराने संबंधी से बिशेष निकटता की अनुभूति करेंगे। ग्रहों की अनुकूलता से अवरोधित कार्य हल होने के आसार हैं।

धनु:– किसी भी प्रयास में आर्थिक अभाव अवरोधक होगा। साहस व बुद्धिमत्ता से पुरानी समस्याओं पर बिजय प्राप्त कर सुख की अनुभूति करेंगे। विषम स्थितियों के मध्य परिश्रम व लगन से प्रगति की ओर अग्रसर होंगे।

मकर :– बुद्धिमत्ता व परिश्रम का मिला–जुला संजोग का भरपूर लाभ उठाएंगे। आर्थिक क्षेत्र में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। सफलताएं आंतरिक क्षमताओं का एहसास कराएंगी। घर में खुशहाल स्थिति प्रसन्न रखेगी।

कुंभ :– शासन–सत्ता में व्यस्तता बढ़ेगी। मन आर्थिक सुदृढ़ता हेतु चिंतित होगा। सामाजिक सक्रियता से मान–प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राजनीति से जुड़े लोगों को ग्रहों की अनुकूलता का लाभ मिलेगा।

मीन :– महत्वाकांक्षी अभिलाषाएं मन में असन्तुष्टि पैदा करेंगी। तामसिक विचारों को मन से दूर रखें। विपरीतलिंगी संबंधों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति में ब्यय अपेक्षित है।

प्रदूषण की कीमत : क्या भारत को चाहिए एक व्यापक 'प्रदूषण कर'?

पर्यावरणीय आपातकाल और सीमित राजस्व-क्या आर्थिक दंड ही हरित भविष्य का मार्ग बना सकता है?''

–डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत आज उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ तेज आर्थिक विकास और बिगड़ते पर्यावरण के संकट के बीच संतुलन बनाना अत्यंत कठिन चुनौती बन गया है। शहरों की हवा दिनदृप्रतिदिन जहरीली होती जा रही है, नदियाँ औद्योगिक कचरे से भर रही हैं, भूमिगत जल स्तर घट रहा है, ठोस कचरे के पहाड़ महानगरों की पहचान बनते जा रहे हैं, वहीं जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या अब भारत को प्रदूषण फैलाने वालों पर प्रत्यक्ष आर्थिक दंड लगानेकृअर्थात् विस्तृत "प्रदूषण कर" लागू करनेकृ की आवश्यकता है? प्रदूषण कर का विचार नया नहीं, परन्तु इसकी आवश्यकता आज पहले से कहीं अधिक है। अर्थशास्त्र में यह माना जाता है कि जब कोई उद्योग, वाहन या गतिविधि प्रदूषण फैलाती है तो उसका दुष्परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ता है, न कि केवल उसे जो प्रदूषण फैला रहा है। यह बाज़ार व्यवस्था की वह गंभीर विफलता है जिसे "बाह्य लागत" कहा जाता हैकृ अर्थात् नुकसान तो समाज को होता है, पर उसका मूल्य न तो वस्तु की कीमत में जुड़ता है, न ही प्रदूषण फैलाने वाला उसे भरता है। ऐसे में "प्रदूषण कर" इसी असंतुलन को सुधारने का प्रयास करता है, जहाँ जो जितना अधिक प्रदूषण फैलाए, वह उतनी अधिक आर्थिक कीमत चुकाए। भारत में कोयले पर लगाया गया "स्वच्छ ऊर्जा उपकर" इसका एक प्रारंभिक स्वरूप था, परंतु आज देश में वायु, जल, ध्वनि, ठोस कचरा और औद्योगिक उत्सर्जन का ऐसा मिश्रित संकट है कि केवल किसी एक क्षेत्र पर कर लगाना पर्याप्त नहीं। आवश्यकता एक सर्वसमावेशी और वैज्ञानिक पद्धति से तैयार प्रदूषण कर की है, जो प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ विकल्पों को बढ़ावा देने में सहायक हो। प्रदूषण कर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रदूषण को महँगा बनाता है और स्वच्छता को सस्ता। जब किसी उद्योग को प्रति इकाई उत्सर्जन पर कर देना पड़ेगा, तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसी तकनीक अपनाने की ओर अग्रसर होगा जो कम प्रदूषण करे। यूरोप जैसे क्षेत्रों में यह प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है जहाँ कार्बन–आधारित दंड के बाद ऊर्जा–संरक्षण और हरित तकनीक का उपयोग अत्यधिक बढ़ा। भारत में भी यह परिवर्तन संभव है, बशर्ते नीति दीर्घकालिक, पारदर्शी और लक्ष्य–उन्मुख हो। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत को आने वाले वर्षों में पर्यावरण–रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा पर बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होगी। नदियों की सफाई, स्वच्छ परिवहन व्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन तथा हरित भवनों के विकास पर अत्यधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। ऐसे में प्रदूषण कर एक स्थायी और अनुमानित राजस्व स्रोत बन सकता है, जिसे एक स्वतंत्र "हरित निधि" के माध्यम से केवल पर्यावरण संरक्षण पर व्यय किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर भी प्रदूषण कर का महत्व बढ़ रहा है। कई विकसित देश अब उन आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लगा रहे हैं जो अधिक प्रदूषणकारी स्रोतों से बनती हैं। यदि भारत घरेलू स्तर पर प्रदूषण पर उचित कर लागू करता है, तो भारतीय निर्यातकों को विदेशी बाज़ारों में अतिरिक्त शुल्क से राहत मिल सकती है। इस प्रकार प्रदूषण कर केवल पर्यावरण–हित में नहीं, बल्कि भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा की रक्षा में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। परंतु इन सबके बीच सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रदूषण कर गरीबों पर भारी पड़ सकता है? यह चिंता बिल्कुल वास्तविक है। यदि ईंधन और बिजली की लागत बढ़ेगी, तो उसके साथ ही परिवहन, खाद्य पदार्थ और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। इसका सीधा प्रभाव निम्न–आय वर्ग पर पड़ता है, जिनके पास विकल्प सीमित होते हैं। इसलिए प्रदूषण कर को न्यायपूर्ण बनाने के लिए यह अनिवार्य होगा कि निम्न–आय वाले परिवारों को प्रत्यक्ष नकद सहायता, ऊर्जा सब्सिडी और रसोई गैस जैसी आवश्यकताओं पर राहत दी जाए। उद्योग जगत की चिंताएँ भी कम नहीं। विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग ऊर्जा–प्रधान होते हैं और किसी भी अतिरिक्त कर का प्रभाव उनकी लागत पर पड़ता है। अतः प्रदूषण कर को चरणबद्ध ढंग से लागू करना होगाकृपहले बड़े उद्योगों पर, फिर धीरे–धीरे छोटे उद्योगों को तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ इस दायरे में लाना होगा। हरित मशीनरी पर अनुदान, ब्याज रहित ऋण, और तकनीकी उन्नयन के लिए मार्गदर्शन इस परिवर्तन को सुगम बना सकते हैं। भारत की प्रशासनिक क्षमता भी एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रदूषण का सटीक मापन, डेटा की विश्वसनीयता और निगरानी तंत्र की पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक होगी। छोटे उद्योगों और गैस–प्रमाणित स्रोतों की निगरानी आज भी चुनौतीपूर्ण है। यदि उत्सर्जन मापन ही विश्वसनीय न हो, तो कर प्रणाली पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत को आधुनिक सेंसर–तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी, डिजिटल उत्सर्जन–पंजीकरण तथा रियल–टाइम निगरानी प्रणाली को मजबूत करना होगा। इसके अतिरिक्त, प्रदूषण कर की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि सरकार इसके राजस्व का उपयोग कहाँ करती है। यदि यह धन सामान्य बजट में विलीन हो गया, तो जनता में अविश्वास बढ़ेगा और नीति का उद्देश्य कमजोर पड़ेगा। इसके लिए एक स्वतंत्र "हरित कोष" का गठन आवश्यक है, जो केवल प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जा, हरित परिवहन और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों पर व्यय हो तथा जिसकी वार्षिक लेखा–परीक्षा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो। राजनीतिक दृष्टि से यह एक साहसिक कदम होगा। किसी भी प्रकार की मूल्य–वृद्धि जनता के बीच असंतोष उत्पन्न कर सकती है। परंतु यह भी सत्य है कि पर्यावरणीय संकट अब इतना गंभीर हो चुका है कि उससे निपटने के लिए कठोर, दीर्घकालिक और दूरदर्शी आर्थिक सुधार आवश्यक हैं। भारत की युवा पीढ़ी सुरक्षित जल, स्वच्छ वायु और स्वस्थ जीवन की मांग कर रही है। इस मांग को नज़रअंदाज़ करना अब संभव नहीं। अंततः यह कहा जा सकता है कि प्रदूषण कर भारत के लिए केवल राजस्व–संग्रह का साधन नहीं, बल्कि एक व्यापक हरित परिवर्तन की दिशा में आवश्यक कदम है। इसे न्यायपूर्ण, पारदर्शी, चरणबद्ध और वैज्ञानिक आधार पर लागू करने से भारत न केवल प्रदूषण कम कर पाएगा, बल्कि अपने विकास मॉडल को भी टिकाऊ, स्वस्थ और पर्यावरण–सम्मत बना सकेगा। यदि इसे सही नीतिगत ढंग से लागू किया गया, तो यह भारत के इतिहास में वह मोड़ साबित हो सकता है जहाँ देश ने आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण को एक–दूसरे का विरोधी नहीं, बल्कि सहयोगी सिद्ध किया।

क्या एआइ सोख रही है नीले ग्रह का पानी ?

–सुनील कुमार महला

आज एआइ(आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का जमाना है। दुनिया में आज एआइ के प्रति प्यास निरंतर बढ़ती चली जा रही है, क्यों कि आज शिक्षा, स्वास्थ्य (हेल्थकेयर), खेती–किसानी, सुरक्षा, बैंकिंग और वित्त, उधोग और निर्माण (इंडस्ट्री एंड मैनुफैक्चरिंग), परिवहन,घर और दैनिक जीवन , मनोरंजन के क्षेत्रों में, सरकारी सेवाओं (गर्वनेंस), पर्यावरण संरक्षण से लेकर हर क्षेत्र में एआइ का बोलबाला हो गया है। मनुष्य धीरे धीरे ही सही एआइ के शिकंजे में फंसता चला जा रहा है। सच तो यह है कि आज दिमाग से तकनीक की दोस्ती लगातार बढ़ रही है। कहा गया है कि विज्ञान वरदान है तो अभिशाप भी है, इसलिए एआइ का उपयोग भी , मानव को विवेकपूर्ण तरीके/ढंग से करना चाहिए, क्यों कि इसके अनेक लाभ भी हैं तो हानियां भी हैं। सबसे बड़ी बात, हमें इस बात का ज़रा सा भी भान नहीं है कि एआइ हमारे नीले ग्रह का पानी सोख रही है। आज मनुष्य एआइ का आदी होता चला जा रहा है और वह कोई भी प्रश्न तकनीक से यानी कि एआइ की सहायता से पूछने लगा है, लेकिन एआइ से पूछा गया एक–एक सवाल लीटरों पानी की खपत कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो एआइ के कारण आज पानी का फुटप्रिंट या यूं कहें कि पानी का इस्तेमाल विस्फोटक ढंग से बढ़ता चला जा रहा है। पाठकों को जानकारी प्राप्त करके हैरानी होगी कि दुनिया भर के डेटा सेंटर हर साल अरबों लीटर पानी कूलिंग सिस्टम में सोख लेते हैं, और 2022दृ23 के बीच एआई ढांचे की जल–खपत में 30दृ40ः की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत में भी नए डेटा सेंटरों के कारण जल–उपयोग मेगालिटर स्तर तक बढ़ने लगा है। यदि एआई का ऐसे ही अंधाधुंध विस्तार होता रहा, तो यह भूजल स्तर को खतरनाक रूप से गिरा सकता है। इसलिए श्सस्टेनेबल एआइश् की तकनीकों, ऊर्जा–कुशल मॉडल तथा जिम्मेदार उपयोग की ओर तत्काल कदम बढ़ाना ही धरती को जल–संकट से बचाने का एकमात्र रास्ता है। बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि एआई और पानी का फुटप्रिंट का आपस में संबंध है। दरअसल, आज के समय में एआई के बढ़ते उपयोग के साथ पानी की खपत एक कम चर्चा किया गया, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा बनकर उभर रहा है। गौरतलब है कि आधुनिक एआई मॉडल–खासकर बड़े लैंग्वेज मॉडल (एलएलएमएज) को ट्रेन करने और चलाने में भारी ऊर्जा के साथ–साथ काफी पानी भी लगता है। अब यहां प्रश्न यह उठता है कि आखिर एआई को पानी क्यों चाहिए ? तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग और इंफरेंस (रनिंग) शक्तिशाली डेटा सेंटरों में होता है। यह डेटा सेंटर 24•7 कंप्यूटिंग के कारण बहुत गर्म हो जाते हैं, इसलिए इन्हें ठंडा करने के लिए बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पानी दो तरह से लगता है। मसलन, एक तो कूलिंग के लिए सीधे पानी का उपयोग किया जाता है। दरअसल, कूलिंग टावर्स में पानी वाष्पीकृत किया जाता है ताकि सर्वर ठंडे रह सकें। दूसरा यह कि विद्युत उत्पादन में भी अप्रत्यक्ष रूप से पानी का उपयोग होता है।दरअसल, बिजली उत्पादन–कोयला/थर्मल/न्यूक्लियर भी काफी पानी खर्च करता है। न केवल पानी बल्कि एआई–डेटा सेंटरों की वजह से ऊर्जा की खपत भी बहुत तेजी से बढ़ रही है।उदाहरण के लिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में डेटा सेंटरों की बिजली खपत लगभग 487 टीडब्ल्यूएच (टेरावॉट–घंटा) थी और एई–विशिष्ट (एआइ) वर्कलोड के कारण यह खपत 50 टेरावॉट घंटा के आसपास थी और 2030 तक यह 554 टेरावॉट घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि कि टेरावॉट घंटा ऊर्जा की एक बड़ी इकाई है, जिसका उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर बिजली खपत या उत्पादन बताने के लिए किया जाता है।सरल शब्दों में कहें तो एक टेरावॉट घंटा से तात्पर्य एक अरब किलोवाट–घंटे से होता है। बहरहाल,पानी की खपत की बात करें तो, 2023 में डेटा सेंटरों ने लगभग 175 बिलियन लीटर पानी का उपयोग किया, और 2030 तक यह अनुमान 664 बिलियन लीटर तक पहुंचने का है। मोर्गन स्टेनले की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2028 तक एआइ–डेटा सेंटरों की पानी की खपत (कूलिंग + बिजली उत्पादन) 1,068 बिलियन लीटर पहुँच सकती है, जो 2024 के स्तर से लगभग 11 गुना अधिक है। वहीं दूसरी ओर यदि हम ऊर्जा की खपत की ओर देखें तो, आज के एआइ वर्कलोडों में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। दरअसल, बड़े मॉडल–ट्रेनिंग से लेकर रोज़मर्रा की इनफेरेंस (प्राप्ति) वर्कलोड तक, दोनों ही ऊर्जा माँग को बढ़ा रहे हैं। आज भारत जैसे विकासशील देश में एआई–डेटा सेंटर्स की तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसके कारण ऊर्जा और पानी पर दबाव बढ़ रहा है।एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एआई–डेटा सेंटर्स की बिजली की मांग 2030 तक लगभग 50 टीडब्ल्यूएच प्रति वर्ष तक पहुंच सकती है।पानी की खपत को लेकर एक्वाटिंया नाम की ब्लॉग रिपोर्ट कहती है कि भारत का डेटा सेंटर पानी उपयोग 2025 में लगभग 150.30 बिलियन लीटर था, जो 2029 तक बढ़कर 358.66 बिलियन लीटर तक पहुँच सकता है। इसके अलावा, बिज़नेस स्टैंडर्ड में एक लेख में बताया गया है कि भारत में डेटा सेंटर क्षमता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है (2027 तक 1.8 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान), और इससे ऊर्जा–पानी दोनों संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है। यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि 1 गीगावाट 1,000 मेगावाट और 1 मेगावाट 1,000 किलोवाट के बराबर होता है। इसलिए 1.8 जीडब्ल्यू का मतलब 1,800 मेगावाट या 18,00,000 किलोवाट हुआ, जो बहुत बड़ी मात्रा की बिजली है, जितनी ऊर्जा बड़े बिजली संयंत्र या पूरे शहर की बड़ी आबादी चला सकती है। बहरहाल,एक अन्य उपलब्ध जानकारी के अनुसार एआई–वर्कलोड की वजह से डेटा सेंटर्स की ऊर्जा खपत पिछले कुछ सालों में लगभग 20ः प्रतिवर्ष बढ़ी है। तक्षशिला इंस्टीट्यूशन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में डेटा सेंटर्स में ठंडा करने (कूलिंग) के लिए पानी की खपत, भारतीय जलवायु की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लगभग 25.5 मिलियन लीटर प्रति मेगावॉट (एमडब्ल्यू) प्रति वर्ष हो सकती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कई डेटा सेंटर ऑपरेटर ऊर्जा और पानी की खपत के संदर्भ में अपने आंकड़े भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं दे रहे हैं। बहरहाल, आज हमारे देश में डेटा सेंटर की कुल क्षमता बहुत तेजी से बढ़ रही है।टीबीएस(द बिजनेस स्टैंडर्ड) की एक रिपोर्ट कहती है कि 2027 तक भारत की डेटा सेंटर क्षमता 1.8 जीडब्लयू तक पहुँच सकती है, जिससे बिजली की मांग बहुत बढ़ेगी। आज बहुत सी डेटा कंपनियां हैं,जो अपने सटीक श्डेटा–सेंटर–स्तरश ऊर्जा खपत और जल उपयोग को इएसजी(एनवायरमेंटल, सोशल एंड गर्वनेंस) रिपोर्ट में खुलकर नहीं दिखातीं। दरअसल, इस मुद्दे पर पारदर्शिता में कमी है।हाल फिलहाल, कहना गलत नहीं होगा कि भारत में एआई के बढ़ते इस्तेमाल से बिजली और पानी की खपत तेज़ी से बढ़ रही है।एआई चलाने वाले डेटा सेंटर और क्लाउड सर्वर बहुत अधिक बिजली खपत करते हैं, क्योंकि दिन–रात हजारों कंप्यूटर चलते रहते हैं। बड़े एआई मॉडल को ट्रेन करने में हजारों घरों जितनी बिजली लग सकती है। दरअसल, सर्वरों को ठंडा रखने के लिए बहुत पानी चाहिए, इसलिए पानी की खपत भी बढ़ रही है ।एक कंप्यूट यूनिट को चलाने में सैकड़ों लीटर पानी खर्च हो सकता है। चूंकि, भारत में डिजिटल सेवाएँ, एआई कंपनियाँ और क्लाउड सिस्टम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसलिए ऊर्जा और पानी की यह माँग आगे और भी बढ़ेगी। इसी वजह से अब सौर ऊर्जा, हरित बिजली और पानी–कुशल डेटा सेंटर की जरूरत पहले से कहीं ज़्यादा हो गई है। अंत में यही कहूंगा कि एआई मॉडलों का पानी–फुटप्रिंट तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया की एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती बनता जा रहा है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि बड़े एआई मॉडल–जैसे जीपीटी–4 आकार के मॉडल को ट्रेन करने में कई लाख लीटर पानी खर्च हो सकता है, जबकि चौटजीपीटी जैसे मॉडलों से 20–50 सवाल पूछने भर में उतना पानी लग जाता है, जितना एक कप चाय बनाने में लगता है। जानकारी के अनुसार यह खपत डेटा सेंटर की लोकेशन, मौसम और कूलिंग तकनीक पर निर्भर करती है। एआई उपयोग बढ़ने का सीधा असर पानी की मांग पर पड़ता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पहले से जल–संकट है। डेटा सेंटर, ऊर्जा उपयोग और पानी की खपत मिलकर एक त्रिकोणीय दबाव बनाते हैं, जिससे टेक कंपनियों के लिए पर्यावरणीय निगरानी और भी जरूरी हो जाती है। इस चुनौती को देखते हुए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियाँ श्वाटर पाज़ीटिवश बनने का लक्ष्य लेकर चल रही हैं और एयर–कूलिंग, इमर्शन कूलिंग व रीसाइकल्ड पानी जैसे समाधान अपना रही हैं। जैसा कि ऊपर भी बता चुका हूं कि भारत में भी एआई और डेटा सेंटरों का विस्तार तेजी से हो रहा है, लेकिन कई राज्यों में पहले से पानी की कमी होने के कारण स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसलिए भविष्य में ऊर्जा–कुशल एआई मॉडल, नवीकरणीय ऊर्जा आधारित डेटा सेंटर, पारदर्शी पानी उपयोग रिपोर्टिंग और स्थानीय जल संरक्षण में टेक कंपनियों की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी होगी। समग्र रूप से देखा जाए तो एआई का बढ़ता जल–फुटप्रिंट एक अहम पर्यावरणीय चेतावनी है, और तकनीक को जिम्मेदार व टिकाऊ बनाकर ही संतुलित विकास संभव है।निष्कर्षतः, एआई का बढ़ता जल–फुटप्रिंट हमें यह याद दिलाता है कि तकनीकी प्रगति के साथ पर्यावरणीय जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बड़े एआई मॉडलों में भारी पानी और ऊर्जा खपत भविष्य के लिए चिंता का विषय है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पहले से ही जल–संकट मौजूद है। इसलिए बहुत ही जरूरी और आवश्यक है कि डेटा सेंटर अधिक कुशल कूलिंग तकनीक अपनाएँ। टेक कंपनियाँ पानी–कार्बन न्यूट्रल लक्ष्यों पर गंभीरता से काम करें, और सरकारें टिकाऊ एआई नीतियाँ विकसित करें। आज एआई के बढ़ते उपयोग से डेटा सेंटरों में ऊर्जा और पानी की खपत तेजी से बढ़ रही है, जिससे हमारे नीले ग्रह के जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम चाहें तो इस समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।पहला तो यह कि हमें एआई सेवाओं का समझदारी से उपयोग करना चाहिए तथा इसके अति–उपयोग से बचना चाहिए।दूसरा, कंपनियों और सरकारों पर ग्रीन डेटा सेंटर, पुनर्चक्रित पानी और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने का दबाव बनाकर समस्या को काफी हद तक हल किया जा सकता है। तीसरा, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को कम–ऊर्जा और कम–पानी वाले एआई मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।चौथा, डिजिटल स्वच्छता–अनावश्यक स्टोरेज, बेकार डेटा और पुराने फाइलों को हटाना–सीधे संसाधन खपत कम करता है। पाँचवा, उपयोगकर्ता के रूप में हम उन प्लेटफॉर्मों का समर्थन करें जो सस्टेनेबल एआई के सिद्धांत अपनाते हैं। छठा, घर–समाज में पानी संरक्षण को बढ़ावा देकर ग्रह पर कुल जल–दबाव घटाया जा सकता है। सातवां, तकनीक और पर्यावरण शिक्षा से जागरूक नागरिक तैयार हों। आखरिकार, एआई मानवता की सुविधा के लिए है, लेकिन तभी तक जब तक हम इसे ज़िम्मेदारी और संतुलन के साथ इस्तेमाल करना सीखते हैं। वास्तव में, हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि केवल जिम्मेदार तकनीकी उपयोग और संसाधनों के संरक्षण के माध्यम से ही हम एआई के लाभों का आनंद लेते हुए एक संतुलित और स्थायी भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।

मिशन–2026 : माओवादी आतंक का खात्मा तय

–कृष्णमुरारी त्रिपाठी अटल

वस्तुतः नक्सलवाद–माओवाद के समूलनाश के पीछे केन्द्र की मोदी सरकार और राज्य की साय सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता है।जो सरेंडर करने वालों का स्वागत भी कर रही है। पुनर्वास भी सुनिश्चित कर रही है। लेकिन अगर माओवादी,आतंक का रास्ता नहीं छोड़ते तो उनका अंत भी तय है। यानी मिशन–2026 पूरी तरह से एक्टिवेट है। 17 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में रामनाथ गोयनका व्याख्यान में भी माओवादी आतंक की समाप्ति का ज़िक्र किया। अर्बन नक्सलियों और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि – "पूरे देश में नक्सलवाद–माओवादी आतंक का दायरा बहुत तेजी से सिमट रहा है, लेकिन कांग्रेस में ये उतना ही सक्रिय होता जा रहा था। आप भी जानते हैं, बीते पांच दशकों तक देश का करीब–करीब हर बड़ा राज्य, माओवादी आतंक की चपेट में, चपेट में रहा। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य था कि कांग्रेस भारत के संविधान को नकारने वाले माओवादी आतंक को पालती–पोसती रही और सिर्फ दूर–दराज के क्षेत्रों में जंगलों में ही नहीं, कांग्रेस ने शहरों में भी नक्सलवाद की जड़ों को खाद–पानी दिया। कांग्रेस ने बड़ी–बड़ी संस्थाओं में अर्बन नक्सलियों को स्थापित किया है।" साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने

भाजपा में बढ़ा डिप्टी सीएम केशव मौर्य का कद

बीजेपी ने साधे एक तीर से कई निशाने, ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं बिहार के पर्यवेक्षक

संवाददाता

लखनऊ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भाजपा में कद और बढ़ गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में बतौर सह प्रभारी बेहतर प्रदर्शन करने के बाद उन्हें वहां पर पार्टी विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। वहां अब पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव खातिर केंद्रीय नेतृत्व ने केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया है। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जारी पत्र के अनुसार केशव मौर्य के साथ ही केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है।केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में ही यूपी

में 2017 का चुनाव लड़ा गया था। तब वह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उस समय 14 साल बाद भाजपा को सत्ता में वापसी हुई थी। पार्टी ने तीन चौथाई बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। उनको महाराष्ट्र विस चुनाव 2019 में भी सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई थी। भाजपा वहां भी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। पश्चिम बंगाल में भी उनको चुनाव प्रबंधन में लगाया गया था।यूपी में भाजपा को पहली बार ओबीसी चेहरे कल्याण सिंह के नेतृत्व में सत्ता हासिल हुई थी। उसके बाद 14 साल बाद 2017 में सरकार बनी तब बतौर प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा था। पार्टी में यह बात उठती रहती है कि ओबीसी वोट बैंक जरूरी है। पार्टी के पास ओबीसी चेहरे होने चाहिए। हिंदुत्व के ध्रुवीकरण के जवाब में विपक्ष लगातार पीडीए का कार्ड खेल रहा है।इस पीडीए कार्ड से विपक्ष को 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी हद तक सफलता भी मिली थी। ऐसे में भाजपा को भी लग रहा है कि किसी तरह पीडीए का तोड़ निकाला जाए। इसी नजरिए से केशव प्रसाद बीजेपी के पास ओबीसी का बड़ा चेहरा है। यूपी के बाद अब पार्टी इसी का लाभ लेने की कोशिश पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कर रही है।

फल की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे में पाया काबू

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में गुडंबा थाना क्षेत्र के 23 नंबर चौराहा स्थित एक दुकान में मंगलवार देर रात करीब 2रू15 बजे आग लग गई। उसके बाद स्थानीय थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकान में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। पुलिस के मुताबिक आग लगने वाली दुकान आदिल नगर निवासी आमीन पुत्र रमजान अली की फल की दुकान थी। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए मांगे गए आवेदन

10 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन

उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.uphed.gov. in पर उपलब्ध है आवेदन पत्र

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की जल्द ही नियुक्ति होगी। इस प्रक्रिया के तहत बायोडाटा समेत आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर शाम छह बजे तक होगी। यह जानकारी उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी ने दी। अध्यक्ष पद के लिए नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा। इच्छुक आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में बायोडाटा समेत प्रार्थना पत्र विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–5, नवीन भवन, कक्ष संख्या–40, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के नाम से पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करना होगा। आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक व अन्य अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति भी संलग्न रहेगी। अध्यक्ष पद की कार्यावधि, आयु, अहर्ता, आवेदन पत्र के प्रारूप आदि जानकारी उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट www. uphed. gov. in पर प्राप्त की जा सकती है। इसमें पद के लिए न्यूनतम अहर्ता की भी जानकारी दी गई है। अध्यक्ष पद के लिए राज्य सरकार के प्रमुख सचिव के पद या उनके समकक्ष पद पर रहे, विश्वविद्यालय के कुलपति हों या रहे हों तथा किसी विश्वविद्यालय के न्यूनतम 10 वर्ष तक आचार्य हों या रहे हों और उनके पास कम से कम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो, ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं।

भाजपा संगठनात्मक लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटती है, वास्तविकता यह है कि पार्टी में फैसले पर्ची से होते हैं : अखिलेश

संवाददाता

लखनऊ। बिहार में सरकार गठन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद

मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाने पर समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को आड़े हाथों लिया है। यादव ने कहा कि भाजपा संगठनात्मक लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पार्टी में फैसले पर्ची से होते हैं। बुधवार को अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए यादव ने व्यंग्य करते हुए कहा, भाजपा ने इनसे जिस पद का वायदा किया था, उसको छोड़कर इन्हें बाकी सारे पद और जम्मिदारियां दी जा रही हैं। जहां पर्ची से फैसला होता है वहां क्या ये पर्ची पढ़ने जा रहे हैं? भाजपा पर्यवेक्षक नहीं दरअसल पर्चीवेक्षक भेजती है। भाजपा और लोकतंत्र विलोम हैं। गौरतलब है कि भाजपा ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बिहार में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इसके साथ ही केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को सह–पर्यवेक्षक बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के अनुसार भाजपा के संसदीय बोर्ड ने यह नियुक्तियां चुनाव की प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के उद्देश्य से की हैं।

संक्षिप्त

तीन नशेड़ियों ने युवक को बेल्टों से पीटा, पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर जांच शुरू की

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में एक युवक को बेल्टों से पीटने का मामला सामने आया है। काजी खेड़ा निवासी अशोक चंद्रा ने ऐन गांव के चन्नू, चंदू पटेल और अभिनव मिश्रा पर गाली–गलौज और मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर एनसीआर (गैर–संज्ञेय रिपोर्ट) दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित अशोक चंद्रा ने बताया कि मंगलवार शाम वह लखनऊ से अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी बाइक की चेन टूट गई, जिसके बाद वह पैदल ही गाड़ी लेकर घर जा रहे थे। इस दौरान उनके चाचा बृजभान चंद्रा भी उनके साथ थे। काजी खेड़ा निवासी अशोक चंद्रा ने ऐन गांव के चन्नू, चंदू पटेल और अभिनव मिश्रा पर गाली–गलौज और मारपीट का आरोप लगाया है। काजी खेड़ा निवासी अशोक चंद्रा ने ऐन गांव के चन्नू, चंदू पटेल और अभिनव मिश्रा पर गाली–गलौज और मारपीट का आरोप लगाया है।पीड़ित के अनुसार, कंजाखेड़ा चौराहे पर पहुंचते ही नशे में धुत चन्नू, चंदू पटेल और अभिनव मिश्रा ने उनसे बेवजह गाली–गलौज शुरू कर दी। जब अशोक चंद्रा ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उन्हें बेल्टों से बुरी तरह पीटा, जिससे उन्हें चोटें आईं।

जनता के सबसे निकट होते हैं विधायक-महाना

इसीलिए उनकी जवाबदेही भी अधिक

संवाददाता

लखनऊ। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन कानपुर के अध्यक्ष एसपी सिंह, महासचिव अवनीश मिश्रा एवं अन्य पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य यूपी विधानसभा की कार्यप्रणाली, संसदीय परंपराओं तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के संचालन की प्रक्रियाओं को नजदीक से समझना था।विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए विधायी व्यवस्था की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "विधायक हमेशा जनता के सबसे निकट होते हैं। इसी कारण उनकी जवाबदेही भी अधिक होती है और वे अक्सर आलोचना के केंद्र में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अन्य संस्थाओं का जनता से प्रत्यक्ष संपर्क कम होता है, जबकि विधायिका सीधे जनता के बीच कार्य करती है। ऐसे में विधायिका के प्रति नकारात्मक सोच लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है।" "जब नागरिक इस भव्य और ऐतिहासिक विधानसभा भवन का भ्रमण करते हैं और इसके स्वरूप, इतिहास एवं गरिमा को समझते हैं, तब सदन की वास्तविक महत्ता का अनुभव होता है। सभी को मिलकर विधायिका के प्रति सकारात्मक धारणा विकसित करनी चाहिए। यद्यपि सभी चुनौतियों का तुरंत समाधान संभव नहीं है, परंतु भविष्य में सुधारों की दिशा में निरंतर प्रयास आवश्यक होंगे। मुझे विश्वास है कि 18वीं विधानसभा अपने कार्य, अनुशासन और योगदान के लिए आने वाले समय में विशेष रूप से उल्लेखित की जाएगी।" प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा परिसर का भ्रमण किया। विधानसभा स्टाफ ने उन्हें मुख्य सभा कक्ष, समिति कक्ष, सेंट्रल हॉल, प्रेस गैलरी एवं अभिलेखागार की संरचना और उपयोगिता के बारे में जानकारी प्रदान की।

दिव्यांग महागठबंधन का प्रदर्शन, सरकारी विभागों की नियुक्ति पर उठाए सवाल

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ में हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर दिव्यांगों ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि सरकारी विभागों में उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा पास करने के बावजूद दिव्यांग होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिली। दिव्यांगों ने पेंशन, आवास और मेडिकल सुविधाओं की भी मांग उठाई। दिव्यांग महागठबंधन के महासचिव अरविंद सिंह के मुताबिक दिव्यांगों के साथ भर्ती, पुनर्वास और अन्य मूलभूत सुविधाओं में भेदभाव किया

जा रहा है। ष्जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा।ष्अरविंद सिंह ने स्पष्ट किया कि केवल नौकरी नहीं, पेंशन, आवास और मेडिकल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी दिव्यांगों के अधिकारों में शामिल हैं, लेकिन सरकार की ओर से अनदेखी की जा रही है।

रिश्वतखोरी से तंग किसान एसडीएम के पैर पकड़कर रोया

बोला–अगला पता होगा श्मशान, लेखपाल पर गलत रिपोर्ट का आरोप

संवाददाता

लखनऊ। मेरठ में प्रशासनिक लापरवाही और रिश्वतखोरी से परेशान एक किसान ने मंगलवार को जमकर हंगामा किया। किसान ने एसडीएम

सदर डॉ. दीक्षा जोशी के कोर्ट के बाहर उनके पैर पकड़ लिए और जमीन पर बैठकर रोने लगा। किसान ने धमकी दी कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला, तो उसका अगला पता श्मशान होगा।मामला थाना सरूरपुर के गांव कालीना निवासी किसान राजीव से जुड़ा है।किसान राजीव का उसके पिता रविंद्र सिंह और सत्येंद्र सिंह के बीच चल रहे जमीन बंटवारे के एक पुराने विवाद से संबंधित है। मामला वर्तमान में एसडीएम सदर डॉ. दीक्षा जोशी की कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने लेखपाल को जमीन की रिपोर्ट पेश करने को कहा था।किसान राजीव ने आरोप लगाया कि लेखपाल सुरेंद्र कुमार ने विपक्षी को फायदा पहुंचाने के लिए गलत और मनमानी रिपोर्ट पेश कर दी है। राजीव ने बताया कि लेखपाल ने इस काम के लिए उनसे 10 हजार रूपये रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत उन्होंने पहले भी प्रशासनिक अधिकारियों से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।जब लेखपाल ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और कोर्ट ने उसे नियमानुसार पाया, तो किसान राजीव ने हंगामा करना शुरू कर दिया और कोर्ट के बाहर धरने पर बैठ गया। एसडीएम सदर डॉ. दीक्षा जोशी किसान को समझाने आईं, तो राजीव ने उनके पैर पकड़ लिए। डॉ. दीक्षा जोशी ने किसान को पानी पिलाया और उसकी समस्या सुनी।किसान राजीव न्याय की मांग पर अड़ा रहा और उसने एडीएम सिटी बृजेश सिंह से बात करते हुए कहा, ष्मुझे प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरा अगला पता अब श्मशान घाट होगा। मैं जान दे दूंगा।ष्कई घंटे तक चले हंगामे के बाद एडीएम सिटी बृजेश सिंह और एडीएम एफआर सूर्यकान्त त्रिपाठी ने किसान को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।एसडीएम सदर दीक्षा जोशी ने बाद में स्पष्ट किया कि किसान तुरंत फैसले की जिद पर अड़ गया था। उसे समझाया गया है कि कोर्ट में दोनों पक्षों को पक्ष रखने का समय दिया जाएगा, इसके बाद ही कोई फैसला होगा।

क्रिकेट क्लबों ने दिखाया पूरा दमखम, टीमों ने हासिल किये पूरे अंक

संवाददाता

लखनऊ। 21वीं बाबू बनारसी दास सी डिवीजन लीग में बुधवार के मुकाबलों में कई क्लबों ने शानदार प्रदर्शन कर पूरे अंक बटोरे। खेले गए मैचों में सोनी क्रिकेट क्लब, स्टैंडर्ड क्रिकेट क्लब, लखनऊ क्रिकेटर्स, गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, एसआरके स्पोर्ट्स क्लब, कंचन स्पोर्ट्स क्लब, राहुल कपूर क्रिकेट अकादमी, आरकेबी क्रिकेट क्लब, गुजराल क्रिकेट अकादमी, लक्ष्मण सिंह क्रिकेट क्लब, हिंदुस्तान फायर क्रिकेट क्लब और आईपीआरके क्लब विजयी रहे। आईपीआरके ने केडी सिंह बाबू स्पोर्ट्स क्लब को 85 रनों से हराया। टीम ने 290 रन बनाए, जिसके जवाब में विरोधी टीम 205 रन ही बना सकी। विजयी टीम से रितेश राय ने 105 गेंदों में 111 रन की पारी खेली। गोसाईगंज में सोनी क्रिकेट क्लब ने दिव्ययुग आश्रम को दस विकेट से मात दी। दिव्ययुग की टीम 70 रन पर सिमट गई। सोनी की ओर से अलौकिक टंडन ने चार विकेट चटकाए और टीम ने बिना विकेट खोए लक्ष्य हासिल किया। लार्ड बालाजी स्टेडियम पर स्टैंडर्ड क्रिकेट क्लब ने अरमान क्रिकेट अकादमी को आठ विकेट से पराजित किया। अरमान की टीम 84 रन पर सिमट गई। स्टैंडर्ड की ओर से हेमंत यादव ने चार विकेट लिये। एनडीबीजी ग्राउंड पर लखनऊ क्रिकेटर्स ने नेशनल यंगस्टर्स को आठ विकेट से हराया। नेशनल यंगस्टर्स की पूरी टीम 64 रन पर आउट हो गई। विजेता टीम से वंश तिवारी ने चार विकेट हासिल किए। स्पोर्ट्स कॉलेज ने लखनऊ स्पोर्ट्स क्लब को छह विकेट से मात दी। लखनऊ स्पोर्ट्स ने 114 रन बनाए, जिसके जवाब में कॉलेज ने चार विकेट खोकर लक्ष्य पा लिया। अंकुल गुप्ता ने छह विकेट लेकर मैच में चमक बिखेरी। एसआरके स्पोर्ट्स क्लब ने फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब को आठ विकेट से हराया। फ्रेंड्स के 141 रन के जवाब में एसआरके ने आसानी से लक्ष्य हासिल किया। विशाल राज ने 25 गेंदों पर 51 रन और शेखर राणा ने 80 रनों की तेज पारी खेली।कंचन स्पोर्ट्स क्लब ने पैंथर्स अकादमी को आठ विकेट से हराया। पैंथर्स के 241 रन के जवाब में कंचन ने दो विकेट खोकर जीत हासिल की। आश्विक सिंह यादव ने 84 गेंदों में नाबाद 156 रन बनाए। राहुल कपूर क्रिकेट अकादमी ने अवध टाइगर्स को 102 रनों से हराया। अकादमी के 195 रन के जवाब में अवध टाइगर्स 93 रन पर ढेर हुए। आशीष शर्मा ने चार विकेट और 17 रन जोड़े। पार्थ क्रिकेट अकादमी ने सिंड्रा क्रिकेट क्लब को 48 रन से हराया। पार्थ की ओर से वेदांत मिश्रा ने 113 रन की शतकीय पारी खेली। आरकेबी क्रिकेट क्लब ने यूनिटी क्लब को 215 रन से हराया। विजेता टीम से कपिल सिंह ने 61 रन और दो विकेट लिये।ओम स्पोर्ट्स क्लब ने ग्रेस अकादमी को सात विकेट से हराया, भूपेंद्र कुमार ने 52 रन बनाए। गुजराल क्रिकेट अकादमी ने सीएसडी सहारा टीम को 14 रन से हराया। अमृत्य रंजन ने 61 रन और तीन विकेट लिये। लक्ष्मण सिंह क्लब ने अवध क्रिकेट अकादमी को सात विकेट से मात दी।

राजधानी में सपाइयों का हंगामा, प्रदर्शन, पुलिस से नोकझोंक

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर समाजवादी पार्टी का जोरदार हंगामा–प्रदर्शन किया। सपा युवजन सभा, सपा छात्र सभा, लोहिया वाहिनी, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी और सदस्यों ने पोस्टर , बैनर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन एक संस्थान के खिलाफ था। कार्यकर्ताओं ने कहा ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। हंगामे के दौरान पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। प्रदर्शन में शामिल सपा नेता अनीस राजा ने कहा कि समाजवादी पार्टी को लगातार टारगेट किया जा रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और नेताजी मुलायम सिंह के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार हो रहा है। पार्टी के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाया जा रहा है जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में सभी लोगों का सम्मान है, अखिलेश यादव हमारे नेता है जो पार्टी के संस्थापकों से लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरा सम्मान और अधिकार देते हैं। जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, हम लोग उसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और आगे भी ये विरोध जारी रहेगा।प्रदर्शन में शामिल मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय यादव ने कहा कि हम लोग अपने नेता के समर्थन में उतरे हैं। मुलायम सिंह के उत्तराधिकारी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के खिलाफ अनावश्यक टिप्पणी और दुष्प्रचार हो रहा है हम इसका विरोध करते हैं। अखिलेश यादव पीडीए के जननायक हैं। सभी दलित, शोषित, वंचित को साथ लेकर चल रहे हैं। बेरोजगारों और पीड़ितों की आवाज है। पीडीए के जननायक इस बार जनता विरोधी शक्तियों को उखाड़ फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी आम लोगों को गुमराह कर रही है। जो जरुरी मुद्दे हैं उनसे आम जनता का ध्यान भटकने के लिए अनावश्यक मुद्दों को मुद्दा बनाया जा रहा है।

मंत्री आवास के पास मां–बेटे ने सल्फास खाया, मथुरा से आए थे, हालत गंभीर

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में पर्यटन मंत्री के आवास के पास बुधवार दिन में 11.30 बजे मां–बेटे ने सल्फास खा लिया। वे सड़क पर गिर गए। हालत बिगड़ने लगी तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया। बेटे को भर्ती कर लिया गया, लेकिन मां की हालत लगातार बिगड़ रही थी इसलिए उन्हें कजीएमयू रेफर किया गया। मां का नाम मुनेश सिंह (56) और बेटे का नाम बलजीत सिंह (38) है। वह मथुरा के बरसाना के रहने वाले हैं। दोनों के पास एक बैग मिला है जिसमें सल्फास के 2 पाउच और 1 मोबाइल फोन था। बेटे की जेब से एक एप्लिकेशन मिली है। इसमें लिखा है– भूमाफिया ने 43 लाख रुपए लेकर प्लॉट नहीं दिया। मकान से भी निकाल दिया। अब धमकी देते हैं कि हमारा कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया मां–बेटे सीएम आवास की तरफ जा रहे थे। लेकिन, पुलिस सुरक्षा को देखते हुए पहले ही जहर खा

लिया। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से इस घटना का कोई कनेक्शन नहीं है। बलजीत की जेब में एक एप्लीकेशन मिली। इसमें लिखा है मथुरा के भूमाफिया जयप्रकाश त्यागी, नरेश त्यागी, पुष्पेंद्र त्यागी, हरि नारायण राय और अभय शर्मा ने उन्हें लूट लिया है। इन लोगों से एक प्लॉट 15 लाख और एक मकान 28 लाख रुपए में खरीदा था। 2 साल हो गए लेकिन मकान की रजिस्ट्री नहीं कराई। बाद में घर से बाहर निकाल दिया। वहीं, प्लॉट पर भी कब्जा नहीं दिया। इनके खिलाफ जब कोर्ट से मुकदमा दायर करवाया तो ये लोग दबंगई करने लगे। हर अधिकारी के पास शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऊपर से ये लोग कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे। उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। 2 पेज की एप्लिकेशन में लिखा है– जब हमने चारों भूमाफिया के खिलाफ भाजपा और मुख्यमंत्री जनता दरबार में शिकायत की तो इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की। मेरी मां के कपड़े फाड़ दिए। उसके बाद जो मकान हमें बेचा उसी मकान से हमें निकालकर हमारे सारे सामान को बाहर फेंक दिया। अब वहां ताला लगा दिया है। हमें धमकी दी है कि अगर हम दोबारा उस मकान की तरफ गए तो हमें जान से मार देंगे। हमारे जीवनभर की कमाई इन लोगों ने लूट ली। हमारी बेइज्जती भी थी। हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी के यहां सल्फास खाकर आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी मौत के जिम्मेदार हरि नारायण, जय प्रकाश त्यागी, नरेश त्यागी, पुष्पेंद्र त्यागी और अभय शर्मा होंगे।

मंडलायुक्त का निरीक्षण, घटिया सड़क निर्माण पर ठेकेदार पर जुर्माना

संवाददाता

लखनऊ। चिनहट द्वितीय वार्ड के विकल्प खंड में हाल ही में निर्मित सड़क की गुणवत्ता पर उठे सवालों ने प्रशासन को हरकत में ला दिया है। पार्षद शैलेन्द्र वर्मा तथा क्षेत्रवासियों की लगातार शिकायतों के बाद शासन के निर्देश पर मंगलवार को मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत व नगर आयुक्त गौरव कुमार ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान तीस लाख की लागत से निर्मित सड़क उखड़ी मिलने पर नगर आयुक्त ने धामी कन्ट्रक्शन पर 50 हजार का जुर्माना ठोक दिया।

एमवे इंडिया ने न्यूट्रीलाइट विटामिन डी प्लस बोरॉन लॉन्च किया

बीएनई

देहरादून। पोषण के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता को और मजबूत करते हुए, एमवे इंडिया, जो स्वास्थ्य और वेलनेस के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है, ने न्यूट्रिलाइट विटामिन डी प्लस बोरॉन लॉन्च किया। यह वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया फ़ॉर्मूलेशन विटामिन डी का स्तर बेहतर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है और हड्डियों तथा इम्यूनिटी को बेहतर करता है। लॉन्च के दौरान एमवे इंडिया के प्रबंध निदेशक, रजनीश चोपड़ा ने कहा, "आजकल की भागदौड़ भरी जीवनशैली और धूप के संपर्क में कम रहने के कारण भारत में विटामिन डी की कमी तेज़ी से बढ़ी है। अध्ययनों से पुष्टि हुई है कि लगभग 80–90 प्रतिशत भारतीयों में विटामिन डी का स्तर अपर्याप्त है, जो समय के साथ हड्डियों और समग्र स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, एमवे में हम विज्ञान आधारित न्यूट्रिशन लाइन को बेहतर बना रहे हैं ताकि लोग अपने स्वास्थ्य लक्ष्य हासिल कर सकें। उत्पाद नवाचार पर रणनीतिक रूप से ध्यान देने के तहत, हमें अपने नए उत्पाद 'न्यूट्रीलाइट विटामिन डी प्लस बोरॉन' को लॉन्च करते हुए गर्व हो रहा है। यह उत्पाद मजबूत हड्डियों और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी तत्वों के साथ तैयार किया गया है। यह हमारे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के कायाकल्प और लंबे समय तक अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी प्रतिबद्धता केवल सप्लीमेंट तक सीमित नहीं है। हम लोगों को उनका स्वास्थ्य बेहतर बनाने, उनकी ऊर्जा बढ़ाने और उन्हें लंबा ही नहीं बल्कि अधिक स्वस्थ और संतोषपूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं।" फ़ॉर्मूलेशन की खूबियों पर बात करते हुए, एमवे इंडिया की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, अमृता असरानी ने कहा, "यह फ़ॉर्मूलेशन वाकई समग्र स्वास्थ्य की हमारी सोच को दर्शाता है। एमवे में हम आधुनिक विज्ञान पर आधारित उन्नत सप्लीमेंट्स देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि स्वास्थ्य के प्रति सजग आजकल के उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी हो सकें। विटामिन डी3 शरीर में कैल्शियम अवशोषण को बेहतर बनाकर हड्डियों की संरचना और घनत्व को मजबूत करता है। बोरॉन विटामिन डी के उपयोग को बेहतर बनाता है, जबकि विटामिन के2 यह सुनिश्चित करता है कि कैल्शियम वहीं पहुँचे जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, यानी हड्डियों में। इसी के साथ, लीकोरिस और क्वेरसेटिन का वह मिश्रण जिसका हमने पेटेंट लिया हुआ है, विटामिन डी3 का पूरक बनकर हड्डियों को और भी बेहतर बनाता है और शरीर को प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट लाभ भी देता है। विटामिन डी3, बोरॉन, विटामिन के2, क्वेरसेटिन और लीकोरिस के अनूठे मिश्रण के साथ, न्यूट्रिलाइट विटामिन डी प्लस बोरॉन केवल सप्लीमेंट्स का काम नहीं करता बल्कि शरीर को कई अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है और पोषण की कमी को समय रहते पूरा करता है। यह उत्पाद अनुशंसित दैनिक खुराक और संबंधित विनियामक मानकों के अनुरूप है, जो दर्शाता है कि न्यूट्रीलाइट लोगों को बेहतर स्वास्थ्य अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर प्रतिबद्ध है।

स्टेयरिंग फेल होने से एक्सप्रेस वे पर बस पलटी तीस यात्री घायल

बृजेश चतुर्वेदी

तिर्वा राजेश कुमार भी मेडिकल कॉलेज

कन्नौज। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे पर बुधवार सुबह करीब 5 बजे एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 30 से 32 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को तिर्वा स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। यह बस दिल्ली से गोंडा जा रही थी, जिसमें लगभग 50 लोग सवार थे। ठठिया थाना क्षेत्र के 210 किलोमीटर पर पहुंचते ही बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। सूचना मिलने पर यूपीडा की पांच एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं और घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। हादसे की जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सीपी पाल और सीएमएस डॉ. दिलीप सिंह ने डॉक्टरों की टीमें लगाकर घायलों का इलाज शुरू कराया। उधर, सीओ तिर्वा कुलवीर सिंह और एसडीएम पहुंचे और घायलों से घटना की जानकारी ली। बस यात्रियों ने बताया कि बस पलटते ही चीख–पुकार मच गई। कई यात्रियों ने शीशा तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास किया। यात्रियों के अनुसार, बस एक्सप्रेस–वे पर तीन बार पलटी खाई। डबल–डेकर बस पर काफी सामान भी लदा हुआ था। यात्रियों ने बताया कि यह हादसा बस का स्टेयरिंग फेल होने के कारण हुआ। घायलों में गोंडा के जमुनापुर्वा कटरा बाजार निवासी फौजदार, मुंशीपुर्वा निवासी राजेश कुमार, ज्ञानतैहा निवासी शुभम, गैगतैहिया निवासी जानवी, कटरा बाजार निवासी अजीत कुमार, देव पलिया निवासी जितेंद्र कुमार, कुंवरपुर करनैलगंज निवासी रामसागर और सतहरी निवासी शुभी समेत कई अन्य लोग शामिल हैं।

एनसीएल की सीडब्ल्यूएस इकाई ने सीएसआर के तहत स्थानीय विद्यालयों में जूतों का किया वितरण

500 से अधिक बच्चों ने उठाया लाभ

बीएनई

सिंगरौली। एनसीएल की सभी परियोजना एवं इकाइयों द्वारा समय–समय पर सीएसआर के तहत स्थानीय परिक्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्य किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में एनसीएल की सीडब्ल्यूएस इकाई द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत अजगूढ़ ग्राम, चितरंगी में स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, अजगूढ़ एवम शासकीय प्राथमिक विद्यालय, पतेरीटोला, अजगूढ़ में विद्यार्थियों को निः शुल्क जूतों का वितरण किया गया। एनसीएल सीडबल्यूएस द्वारा यह कार्य बढ़ती ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए किया गया। इस दौरान लगभग 570 विद्यार्थियों ने वितरण का लाभ उठाया । इस अवसर पर परियोजना से नोडल अधिकारी (सीएसआर) एवं स्कूल के प्राचार्य तथा अन्य लोग उपस्थित रहे। गौरतलब है कि एनसीएल सीएसआर के तहत स्थानीय परिक्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कौशल विकास, पेय जल व आधारभूत ढांचे के निर्माण जैसे अनेक कार्य कर रही है ।

103 नर्सिंग अधिकारी व 30 डेंटल हाईजिनिस्ट के पदों पर निकली भर्ती

चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने जारी किया भर्ती विज्ञापन

बीएनई

देहरादून। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को शीघ्र ही 103 नये नर्सिंग अधिकारी मिलेंगे। नर्सिंग अधिकारियों (महिला/पुरूष) के बैकलॉग के इन पदों पर सीधी भर्ती के लिये राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है। जिसके लिये ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसम्बर, 2025 को निर्धारित की गई है। नर्सिंग अधिकारियों के बैकलॉग के इन पदों को भरे जाने से प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के चिकित्सा इकाईयों में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत होगी वहीं मरीजों की देखभाल में और अधिक सुधार होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की सक्रियता एवं विभागीय मॉनिटरिंग के चलते स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारियों (महिला/पुरूष) के बैकलॉग के 103 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिस हेतु उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड ने भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है। चयन बोर्ड ने उक्त भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 02 दिसम्बर 2025 से शुरू करने तथा अंतिम तिथि 22 दिसम्बर 2025 निर्धारित की है। सीधी भर्ती में नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिप्लोमाधारी के लिये 63 पद निर्धारित किये गये हैं। इसके अलावा नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिग्रीधारक के लिये 31 पद, नर्सिंग अधिकारी (पुरूष) डिप्लोमाधारक 05 व नर्सिंग अधिकारी (पुरूष) डिग्रीधारक के लिये 04 पद हैं। इसस पहले राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारियों के रिक्त 587 पदों पर भर्ती निकाली है। इस प्रकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग व चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग अधिकारियों के कुल 690 पदों पर शीघ्र भर्ती की जायेगी। जिसके उपरांत चयनित नर्सिंग अधिकारियों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों व प्रदेशभर के विभिन्न चिकित्सा इकाईयों में नियुक्ति दी जायेगी। जिससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक मजबूत होंगी साथ ही मरीजों की देखभाल में भी खास सुधार होगा। डेंटल हाईजिनिस्ट के 30 पदों पर भी निकली भर्ती चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत डेण्टल हाईजिनिसट के रिक्त 30 बैकलॉग के पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग द्वारा राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को उक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिये अधियाचन भेजा गया था। जिसके क्रम में चयन बोर्ड ने आज (बुधवार) को भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है। विज्ञापित 30 पदों में अनारक्षित वर्ग के 04, अनुसूचित जाति 14, अनुसूचित जनजाति 03 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग 9 पदों पर भर्ती की जायेगी। जिसके लिये चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। जिसके तहत अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर 03 दिसम्बर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उक्त भर्ती के लिये आवेदन की अंतिम तिथि 23 दिसम्बर 2025 निर्धारित की गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में भी नर्सिंग अधिकारियों के 103 पदों पर भर्ती होगी। इस प्रकार दोनों विभागों में नर्सिंग अधिकारियों के कुल 690 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में डेण्टल हाईजिनिस्ट के 30 पदों पर भी भर्ती शुरू कर दी है। नर्सिंग अधिकारी व डेंटल हाईजिनिस्ट आने से अस्पतालों में रोगियों की देखभाल की गुणवत्ता बढ़ेगी, उपचार सेवाएँ सुदृढ़ होंगी और आमजन को समयबद्ध बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी। – डॉ. धन सिंह रावत, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड।

एसआईआर का दो जगहों से फॉर्म भरा तो एक साल की सजा होगी

बृजेश चतुर्वेदी

कन्नौज। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में मतदाता दो–दो स्थानों से गणना प्रपत्र न परें। अगर ऐसा किया तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा–31 के तहत एक वर्ष तक की सजा दी जा सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में गांव या शहर और दो–दो राज्यों की मतदाता सूची में नाम है तो भी सिर्फ एक जगह से ही गणना प्रपत्र भरकर जमा करें। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने बताया कि चुनाव आयोग दो–दो जगह से गणना प्रपत्र भर जमा करने वालों को आसानी से पकड़ लेगा। डिजिटल माध्यम से इसकी फूलपुफ व्यवस्था की गई है। आप पुश्तैनी गांव में मतदाता बुनकर वोट डालना चाहते हैंतो वहां से फॉर्म भरकर जमाकरें। या शहर में रहना चाहते है तो वहां से फार्म भरें। यूपी में चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं को आसानी से पकड़ लेगा बीते 27 अक्तूबर को मतदाता सूची फ्रीज की गई है। वर्तमान में इस सूची में जहां नाम है, वहीं से फॉर्म भरें। यूपी का जिसका रहने वाला कोई दूसरे राज्य मुंबई, दिल्ली या फिर अन्य राज्य में रह रहा है और वहां वोटर है तो फिर यहां गणना प्रपत्र न भरे। क्योंकि एसआईआर मतदाता सूची से मृत व्यक्तियों के नाम बाहर करने व जिन मतदाताओं के दो–दो जगह नाम हैं, उनके नाम एक जगह से हटनि इत्यादि के लिए किया जा रहा है। फर्जी और मृत वोटरों का एआई से पता लगाएगा निर्वाचन आयोग एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने फर्जी या मृत मतदाताओं को शामिल होने से रोकने के लिए एआई आधारित सत्यापन प्रणाली शुरू करने का फैसला किया है। एआई प्रणाली मतदाता डाटाबेस में तस्वीरों में चेहरे का विश्लेषण कर कई स्थानों पर पंजीकृत व्यक्तियों की पहचान में मदद करेगी। अधिकारी ने बताया, मतदाताओं की तस्वीरों के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें बढ़ी हैं। कई स्थानों पर एक ही मतदाता की तस्वीर पाए जाने की घटनाओं का पता लगाने के लिए एआई फेशियल मैचिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसी बीच कन्नौज के जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री की ओर से एक पम्पलेट भी वितरित कराया जा रहा है इसका शीर्षक है समस्त मतदाताओं एवं बूथ लेविल अधिकारियों हेतु आवश्यक सूचना 1–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा–31 के अन्तर्गत किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि के, अथवा किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें अपवर्जित किए जाने के संबंध में, ऐसा कथन या ऐसी घोषणा लिखित रुप में करेगा जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे होने का विश्वास नहीं है. तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा–32 के अन्तर्गत यदि कोई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर या अन्य व्यक्ति जो किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि से संसक्त या किसी प्रविष्टी को उस निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने या उससे अपवर्जित करने से संसक्त किसी पदीय कर्तव्य के पालन के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, ऐसे पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य या कार्यलोप का दोषी युक्तियुक्त हेतुक के बिना होगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी, किंतु दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय होगा।

परस्पर विश्वास और सामंजस्य के बदौलत 'कंपनी और कम्यूनिटी' दोनों समृद्धि की ओर अग्रसर- श्री साईराम, सीएमडी एनसीएल

जयंत परियोजना विस्तार हेतु 'प्रतिकर वितरण' का हुआ शुभारंभ

बीएनई

सिंगरौली। विकसित भारत की पृष्ठभूमि में देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोयला उत्पादन अनिवार्य है। इसी कड़ी में भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी – एनसीएल, जयंत परियोजना विस्तार के तहत भू–अर्जन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। बुधवार को एनसीएल मुख्यालय में जयंत परियोजना विस्तार हेतु 'प्रतिकर वितरण' का शुभारंभ करते हुए 33 परिवारों को अनुमोदित स्कीम के अनुसार देय प्रतिकर राशि का आंशिक भुगतान अग्रिम राशि के रूप में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएमडी एनसीएल बी साईराम ने कहा कि परस्पर विश्वास और सामंजस्य के बदौलत 'कंपनी और कम्यूनिटी' दोनों समृद्धि की ओर अग्रसर होते हैं, जयंत परियोजना विस्तार इसका जीवंत उदाहरण है । प्रतिकर वितरण' शुभारंभ को मोरवावासियों व एनसीएल, दोनों के लिए एतिहासिक बताते हुए उन्होने विभिन्न मंचों के साथ, जनप्रतिनिधियों, राज्य शासन, जिला प्रशासन व हितग्राहियों के निरंतर सहयोग एवं बहूमूल्य सुझावों के लिए कृतज्ञता ज्ञपित की। कार्यक्रम में निदेशक (मानव संसाधन) मनीष कुमार ने आज के दिन को जयंत विस्तार की दिशा में मील का पत्थर बताया और भरोसा दिया कि आगे भी एनसीएल इसी गति के साथ प्रभावित हितग्राहियों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ जयंत परियोजना विस्तार पर कार्य करती रहेगी। इस अवसर पर कार्यक्रम में निदेशक (वित्त) रजनीश नारायण, निदेशक(तकनीकी/संचालन) सुनील प्रसाद सिंह, निदेशक (तकनीकी/परियोजना एवं योजना) आशुतोष द्विवेदी, मुख्य सतर्कता अधिकारी, अजय कुमार जायसवाल, विभिन्न मंचों के प्रतिनिधिगण, स्थानीय पार्षद व अन्य उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि 'जयंत परियोजना विस्तार' का मार्ग जिस त्याग, सहयोग और समझदारी से प्रशस्त हो रहा है, उसका श्रेय परियोजना प्रभावित सम्मानित भू–स्वामियों एवं परिसंपत्ति धारकों को जाता है। उनका योगदान देश की ऊर्जा–आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव है। इसी भावना के साथ, एनसीएल द्वारा प्रदान किया जा रहा 'प्रतिकर वितरण' मात्र स्वीकृति पत्र नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और राष्ट्रीय योगदान के प्रति एनसीएल का कृतज्ञतापूर्ण "आभार पत्र" है। एनसीएल, परियोजना प्रभावित प्रत्येक हितग्राही का हृदय से धन्यवाद करती है, क्योंकि उनका सहयोग... राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा का आधार है। कार्यक्रम का आयोजन महाप्रबंधक निरंजन रुक्मांगद के नेतृत्व में सिंगरौली पुनर्स्थापन सेल ने किया।

संक्षिप्त

फोटो और क्यूआर कोड वाला आधार जारी करने पर विचार कर रहा यूआईडीएआई, फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने लोगों की तस्वीर और क्यूआर कोड के साथ आधार कार्ड जारी करने पर विचार कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य लोगों के डाटा का दुरुपयोग रोकने और वर्तमान आधार कानून के उल्लंघन में ऑफलाइन सत्यापन प्रथाओं को खत्म करना है। आधार अधिनियम ऑफलाइन सत्यापन के मामले में किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति की आधार संख्या या बायोमेट्रिक जानकारी के संग्रह, उपयोग या भंडारण पर प्रतिबंध लगाता है। आधार के लिए नए एप पर एक हुए ऑनलाइन सम्मेलन में, यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार ने कहा, प्राधिकरण दिसंबर में एक नया नियम लाने पर विचार कर रहा है ताकि होटल, इवेंट ऑर्गनाइजर्स की ओर से ऑफलाइन सत्यापन को हतोत्साहित किया जा सके। व्यक्तियों की गोपनीयता बनाए रखते हुए आधार का उपयोग करके आयु सत्यापन प्रक्रिया को बढ़ाया जा सके। कुमार ने कहा, इस बात पर एक सोची–समझी प्रक्रिया चल रही है कि कार्ड पर कोई भी विवरण क्यों होना चाहिए। इसमें सिर्फ एक तस्वीर और एक क्यूआर कोड होना चाहिए। अगर हम छपाई करते रहेंगे, तो लोग छपी हुई चीजें ही लेते रहेंगे। जो लोग इसका दुरुपयोग करना जानते हैं, वे इसका दुरुपयोग करते रहेंगे। आधार को दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए कुमार ने कहा, आधार कार्ड की प्रति का इस्तेमाल कर ऑफलाइन सत्यापन को खत्म करने के लिए कानून पर काम चल रहा है, जिसे एक दिसंबर को आधार प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा, आधार को कभी भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसे सिर्फ आधार संख्या से प्रमाणित किया जाना चाहिए या क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके सत्यापित किया जाना चाहिए। अन्यथा, यह एक नकली दस्तावेज हो सकता है। यूआईडीएआई ने बैंकों, होटलों, फिनटेक फर्मों समेत कई हितधारकों के साथ संयुक्त बैठक की, ताकि उन्हें नए एप के बारे में जानकारी दी जा सके, जिसके जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। आधार अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति का आधार नंबर या बायोमेट्रिक जानकारी ऑफलाइन सत्यापन के लिए इकट्ठा, उपयोग या संग्रहित नहीं की जा सकती। फिर भी कई संस्थाएं आधार कार्ड की फोटोकॉपी इकट्ठा और स्टोर करती हैं।

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने किया बेबी बॉय का नामकरण, फैंस को दिखाई पहली झलक

एजेंसी

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने 19 अक्तूबर को पहली संतान के रूप में बेटे का स्वागत किया। दिवाली से एक दिन पहले कपल के घर किलकारी गूंजी और त्योहार की खुशियां कई गुना बढ़ गईं। अब एक महीने बाद आज 19 नवंबर को कपल ने अपने बेबी बॉय की पहली झलक दिखाई है। साथ ही यह भी बताया है कि अपने बेटे का उन्होंने क्या नाम रखा है? जानिए परी और राघव ने बेटे के साथ दिए पोज परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने आज बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक साझा पोस्ट शेयर किया है। इसमें परिणीति और राघव बेबी बॉय के साथ पोज देते दिख रहे हैं। हालांकि, कपल ने बेटे का चेहरा रिवील नहीं किया है। परी और राघव अपने बेटे के नन्हे पैरों को चूमते दिख रहे हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि बेटे का नाम उन्होंने नीर रखा है। सेलेब्स ने दिए रिएक्शन पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा है, जलस्य रूपम, प्रेमस्य स्वरूपम– तत्र एव नीर। हमारे दिलों को जीवन की एक अनंत बूंद में शांति मिली। हमने अपने बेटे का नाम श्नीरश रखा है। शुद्ध, दिव्य और असीम। कपल के पोस्ट पर भारती सिंह, गौहर खान और निम्रत कौर सहित तमाम सेलेब्स ने रिएक्शन दिए हैं और बेबी बॉय को दुआएं दी हैं।

इस वित्त वर्ष जीडीपी के 1.7% पर पहुंच सकता है चालू खाता घाटा, उच्च टैरिफ और महंगे आयात का दबाव

एजेंसी

नई दिल्ली। टैरिफ दबाव के कारण देश का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर जीडीपी के 1.7 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। बैंक ने पहले 1. 2 प्रतिशत का अनुमान लगाया था। चालू खाता घाटा (CAD) तब होता है जब किसी देश के वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी के आयात का कुल मूल्य उसके निर्यात और अन्य आय के कुल मूल्य से अधिक होता है। यह दर्शाता है कि देश में आने वाले धन की तुलना में देश से बाहर जाने वाला धन अधिक है। त्योहारी मांग के कारण व्यापार घाटे को कुछ दबाव पड़ा रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि त्योहारी मांग के कारण व्यापार घाटे पर कुछ दबाव पड़ने की संभावना है। हालांकि, वस्तुओं, खासकर तेल की कम कीमतें, समग्र प्रभाव को सीमित करने में मदद कर सकती हैं। तेल की कीमतों में उतार–चढ़ाव भारत के लिए सकारात्मक बैंक ने कहा कि तेल की कम कीमतों से भारत के बाहरी संतुलन को मदद मिल सकती है, क्योंकि देश का चालू खाता कच्चे तेल की कीमतों में उतार–चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। रिपोर्ट के अनुसार कच्चे तेल की कीमतों में हर 10 डॉलर प्रति बैरल के उतार–चढ़ाव से भारत के सालाना करंट अकाउंट बैलेंस पर लगभग 15

अरब डॉलर का असर पड़ता है। यानी तेल की कीमतें कम होने पर भारत के व्यापार समीकरणों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि, रिपोर्ट ने आगाह किया कि कमोडिटी कीमतों, खासकर क्रूड में उतार–चढ़ाव, और अमेरिका–भारत व्यापार समझौते में जारी गतिरोध के चलते निर्यात कमजोर रहने का खतरा CAD के अनुमानों पर दबाव डाल सकता है। भारत–अमेरिका व्यापार समझौते के जल्द पूरा होने की उम्मीद इसमें में यह भी बताया गया है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743